(d) Steps are being taken to ensure that the new Excise Policy for Tribal areas forms an integral part of the Tribal Sub-Plans.

New Administration Policy for Tribal Areas for Implementation of ITDPs and other Development Programme

1347. SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether Government have adopted a new Scheme for tribal areas to implement the ITDPs and other development programmes in the new economic schemes;

(b) if so, the main feature thereof;

(c) whether all the States having Sub-plan areas have adopted the same; and

(d) if so, whether Government of Orissa have proposed restructuring of the administrative machinery in ITDPs areas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI I. K. GUJRAL): (a) The Draft Fifth Five Year Plan Document states in the Chapter XIII, page 276, para 13.19 that the "Administrative set up in tribal areas will be restructured to suit the special requirement. It is essential that formulation and implementation of area development plan is entrusted to a single line agency."

(b) In the quidelines sent to the State Governments they were advised to take into consideration local conditions, the existing administrative structure and other institutions while formulating policies for administration. It has been stated that multiplicity of agencies has resulted in the diffusion of responsibility, inadequate control, lack of coordination and from the people's angle, difficulty in identifying the officials concerned with specific programmes. Therefore, the States were requested to evolve an administrative set up to achieve functional coordination and efficiency. Delegation of authority, specificity of responsibility and adequate flexibility would require to be built into the system so as to enable the implementing authority to effect changes in the on-going programmes on the basis of concurrent evaluation. The State Governments were required to spell out this approach clearly in their sub-plans regarding administrative re-organization and personnel policies in the tribal areas.

(c) All the States and Union Territories having substantial tribal population are in the process of finalising their sub-plans including the administrative set up.

(d) The Government of Orissa also is in the process of finalising the sub-plan and personnel policy in the I.T.D.P. areas.

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामों का विद्युतीकरण और विद्युतचालित पम्पों का लगाया जाना

1348. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ऊर्जा उपभोग की राष्ट्रीय गोष्ठी में सरकार ने विचार व्यक्त किया था कि पांचवी पचवर्षीय योजना के अन्त तक 250,000 गांवों को बिजली दी जायगी तथा 40 लाख विदयुत्चालित पम्प गांवों मे लगाय जायेगे ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने गांवों में बिजली पहुंच चुकी है और कितने विदयुत्चालित पम्प लगाये गय है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) देश में 30 नवम्बर, 1975 तक 1,70,274 गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं और 27,17,223 पम्प सेटों को बिजली दी जा चुकी है ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ दायर किए गए मामले

1349. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में 64 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की सिफारिश की है जो विभिन्न विभागों में उच्च पदों पर हैं ,

(ख) उन विभागों के नाम क्या हैं जिनमें ये अधिकारी काम कर रहे हैं , और

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जुलाई, से नवम्बर, 1975 तक कितने राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ मुकद्दमे दायर किये ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों ने नवम्बर, 1975 मास के दौरान 64 राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध जांच के मामलों में जांच पड़ताल / ग्रारम्भिक जांच की कार्यवाही आरम्भ की ।

(ख) ये अधिकारी निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों में कार्य कर रहे हैं —

रक्षा मंत्रालय	6	अधिकारी
वित्त मंत्रालय	5	,,
रेल मंत्रालय	3	,,
निर्माण तथा आवास मंत्रालय	2	अधिकारी
वाणिज्य मंत्रालय	1	,,
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	1	,,
नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय	1	,,
गृह मंत्रालय	1	,,
डाक तथा तार	3	,,
सार्वजनिक उपक्रम	32	,,
संघ राज्य क्षेत्र	6	,,
नागालैंड राज्य सरकार	3	,,
	64	

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों ने जुलाई 1975 से नवम्बर, 1975 तक 57 राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालयों में आरोप पत्र दायर किए ।

एच० एम० टी० घड़ियां

1350. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के बंगलौर एवं श्रीनगर स्थित कारखानों में 1974-75 तथा 1975-76 में दिसम्बर तक कितनी घड़ियों का निर्माण किया गया; और

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने 1974-75 और 1975-76 में कितनी घड़ियों का निर्यात किया तथा यह निर्यात किन-किन देशों को किया गया ?